

५५

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक RN/0-2/R/1051/1994 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 23-7-1994 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग,
रीवा - प्रकरण क्रमांक 117/1985-86 निगरानी

1- बद्रीप्रसाद 2- शोभनाथ पुत्रगण मुरलीराम
निवासी ग्राम कपुरहाई तहसील अमरपाटन
जिला सतना मध्य प्रदेश
विरुद्ध

---आवेदकगण

1- कौशलकिशोर पुत्र यदुनन्दन प्रसाद
2- चिन्तामणि पुत्र यदुनन्दन प्रसाद
दोनों ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन
जिला सतना मध्य प्रदेश

--अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्री आर०एस०तौमर अभिभाषक)

(अनावेदकगण की ओर से श्री बिनोद श्रीवास्तव अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक - 11-01-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण
क्रमांक 117/1985-86 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-7-1994
के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत
प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि ग्राम कपुरहाई तहसील अमरपाटन
की भूमि सर्वे नंब 173, 175, 182, 174 नायब तहसीलदार वृत्त
मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन ने पुराने कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी
स्वत्व प्रदान किये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन
के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण

क्रमांक 5 अ-74/1977-78 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-9-79 से अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसील में पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण क्रमांक 6 अ 74/1979-80 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-86 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 117/1985-86 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-7-1994 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन का प्रकरण क्रमांक 5 अ-74/1977-78 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-9-79 (Remand Order) प्रत्यावर्तन आदेश है। इस आदेश को अपर कलेक्टर सतना ने इसलिये हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है क्योंकि उक्त भूमि में हितबद्ध पक्षकार की सुनवाई हेतु आहुत किये जाने में नायव तहसीलदार ने इस कानूनी मान्यता का पालन करने में तत्परता प्रदर्शित नहीं की थी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की कंडिका 2 में अंकित है कि जिस प्रकार इस भूमि पर हितधारण करने वाले पक्षकार को तहसीलदार द्वारा की जाने वाली जांच के समय आहुत नहीं किये गये हैं। आदेश के पद 5 में उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि अपीलार्थी का विवादगस्त भूमि पर हित था यह अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है इसलिये वह अपील प्रस्तुत करने के लिये सक्षम था। इसी प्रकार अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 117/1985-86 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-7-1994 के पद 2 में विवेचित किया है कि

भूमि शासकीय थी और कब्जे के आधार पर नामान्तरण चाहा जा रहा था एस0डी0ओ0 ने प्रकरण में पेश रिकार्ड से अन्य पक्षकारों को हितबद्ध पाकर उन्हीं भी सुने जाने हेतु रिमान्ड किया था। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-9-79 में , अपर कलेक्टर सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-7-86 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-7-1994 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है एवं अनुविभागीय अधिकारी के (Rimand Order) प्रत्यावर्तन आदेश के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को विचारण न्यायालय में पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण इस निगरानी प्रकरण में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/1985-86 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2-7-1994 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।


(एस0एस0अली)

सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर